



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227]

नई दिल्ली, बंगलवार, अक्टूबर 25, 2011/कार्तिक 3, 1933

No. 227]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2011/KARTIKA 3, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुल्कात संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 2011

विषय : चीन जनवादी गणराज्य से कोलिन क्लोराइड के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

फा. सं. 14/09/2011-डीजीएडी:—मै. जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लि., नोएडा ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटिवस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क का अभिज्ञान, आकलन एवं वसूली तथा शुल्क निर्धारण हेतु) नियम, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात् नियम कहा जाएगा) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा जाएगा) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने चीन जनवादी गणराज्य से कोलिन क्लोराइड के पाटन का आरोप लगाया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने तथा पाटनरोधी उपाय लागू करने का अनुरोध किया है।

2. घरेलू उद्योग की स्थिति : यह याचिका मै. जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लि. द्वारा दायर की गई है जिनका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट सं. 1-ए, सेक्टर 16-ए, इंस्टिट्यूशनल एरिया, नोएडा-201301 में अवस्थित है और कोलिन क्लोराइड के विनिर्माण के लिए विनिर्माण सुविधाएँ सामलय, वडोदरा में अवस्थित है। आवेदक, मै. जुबिलेंट लाइफ साइंसेज लि. का देश के कोलिन क्लोराइड के घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा है। अतः आवेदक नियम 5(क) और (ख) तथा नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग की ओर से याचिका दायर करने की प्रतीता रखते हैं।

3. शामिल उत्पाद : वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद पशु चारे के रूप में सभी स्वरूपों एवं सांद्रणों में उपयोग में लाया जाने वाला कोलिन क्लोराइड (जिसे यहाँ संबद्ध वस्तु कहा गया है) है। कोलिन क्लोराइड एक क्वाटरनरी अमोनियम लवण है जो रंगहीन, लसीला और अत्यंत क्षारीय होता है। इसे पशु चारे में योगज के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इस उत्पाद को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के सीमाशुल्क उप-शीर्ष 2309.9010 तथा 2923.1000 के तहत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और किसी भी प्रकार से वर्तमान जांच के कार्यक्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

4. **घरेलू समान उत्पाद :** आवेदक ने दावा किया है कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं तथा संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएँ और संबद्ध देश से आयातित वस्तुएँ वास्तविक एवं रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण एवं विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के संदर्भ में तुलनीय है। यह दोनों वस्तुएँ तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों उत्पादों को एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग में ला रहे हैं। अतः इस जांच के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमों के अर्थ के भीतर आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं को संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद माना जा रहा है।

5. **शामिल देश :** वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण. है (जिसे एतदपश्चात संबद्ध देश कहा गया है)।

6. **सामान्य मूल्य :** आवेदक ने कहा है कि चीन एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था है और किसी भी देश ने विस्तृत मूल्यांकन मापदंडों का पालन करते हुए चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया है। आवेदक द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत ने चीन के विरुद्ध शुरू की गई लगभग सभी जांचों में चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना है और इसलिए वर्तमान जांच में भी उसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश ही माना जाना चाहिए। आवेदक ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना के अभाव में आवेदक बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में कीमत या परिकलित मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करने की स्थिति में नहीं है और इसलिए उसने सामान्य मूल्य की गणना की है। प्राधिकारी ने इस जांच की शुरूआत के प्रयोजनार्थ परिगणित मूल्य के आधार पर संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य पर प्रथम दृष्ट्या विचार किया है।

7. **निर्यात कीमत :** आवेदक ने आईबीआईएस, मुम्बई द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर निर्यात कीमत निर्धारित की है। कारखाना द्वारा स्तर पर निवल निर्यात कीमत निकालने के लिए निर्यात कीमत में समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन प्रहस्तन और अंतर्देशीय परिवहन हेतु समायोजन किया गया है।

8. **पाटन मार्जिन :** पाटनरोधी जांच की शुरूआत को सही ठहराने के लिए आवेदक ने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से बहुत अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

9. **“क्षति” एवं कारणात्मक संबंध :** आवेदक ने दावा किया है कि वास्तविक क्षति तथा उसका खतरा कथित पाटन के परिणामस्वरूप है। यह दावा किया गया है कि आयातों में सापेक्ष रूप से तथा भारत में खपत के संबंध में वृद्धि हुई है और कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में काफी कटौती हो रही है तथा घरेलू उद्योग की कीमतों का अवमूल्यन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आवेदक ने बाजार हिस्से, लाभ तथा लगाई गई पूंजी पर आय के अनुसार घरेलू उद्योग के निष्पादन में क्षरण का भी दावा किया है।

10. पाटनरोधी नियमों के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरूआत को उचित ठहराने के लिए संबद्ध देश से पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही “क्षति” के पर्याप्त साक्ष्य हैं।

11. **पाटनरोधी जांच की शुरूआत :** उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी पाते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को “क्षति” तथा पाटन एवं “क्षति” के बीच कारणात्मक

संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जांच को उचित ठहराते हैं । तदनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा कथित पाटन की मौजूदगी, व्यापकता एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी उपाय की उस राशि, जिसे यदि लागू किया जाए तो घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी नियमों के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी “ क्षति ” की जांच शुरू करते हैं ।

12. जांच की अवधि (पीओआई) : वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 है । तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 07-मार्च, 08, अप्रैल, 08-मार्च, 09, अप्रैल, 09-मार्च, 10 और जांच की अवधि (पीओआई) अर्थात् 1 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 शामिल होगी । वास्तविक क्षति के जोखिम हेतु पीओआई के बाद की अवधि से संबंधित आंकड़ों की जांच भी की जाएगी ।

13. सूचना प्रस्तुत करना : संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों और भारत में उनके दूतावास/आर्थिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र के जरिए उनकी सरकार, भारत में ज्ञात समझे जाने वाले आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को संगत प्रपत्र में एवं निर्धारित ढंग से सभी सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है । कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय-सीमा के भीतर निम्नलिखित को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से जांच से संगत निवेदन कर सकता है :-

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य एवं उद्योग भंत्रालय

वाणिज्य विभाग

कमरा नं. 240, उद्योग भवन

नई दिल्ली-110107

14. समय-सीमा : वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना तथा सुनवाई हेतु कोई भी अनुरोध लिखित में भेजा जाना चाहिए जो प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन (चालीस दिन) के भीतर पहुँच जाना चाहिए । यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, पाटनरोधी नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में “ उपलब्ध तथ्यों ” के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं ।

15. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना : यदि प्रस्तावली के उत्तर/निवेदन के किसी भाग के लिए गोपनीयता का दावा किया जाता है तो उसे दो अलग-अलग सेटों में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा (क) गोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) तथा (ख) दूसरा सेट अगोपनीय के रूप में चिह्नित (शीर्षक सूची पृष्ठ सं. इत्यादि सहित) । प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से “ गोपनीय ” अथवा “ अगोपनीय ” चिह्नित होना अनिवार्य है ।

16. किसी चिह्न के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को आगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी के पास अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का अवलोकन करने की अनुमति देने का अधिकार होगा । गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों रूपांतरों की दो-दो प्रतियाँ अवश्यक प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

17. जिस सूचना के लिए गोपनीयता का दावा किया गया हो; उस सूचना के प्रदाता द्वारा प्रस्तुत सूचना के साथ समुचित कारणों सहित इस आशय का एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है तथा/अथवा ऐसी सूचना का सारांश तैयार करना क्यों संभव नहीं है ।

18. अगोपनीय सूचना, गोपनीय सूचना की प्रकृति होना अपेक्षित है जिसके साथ गोपनीय सूचना को, उस सूचना के आधार पर जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचीबद्ध किया जाए या रिक्त छोड़ दिया जाए/संक्षेप में बताया जाए । अगोपनीय सारांश गोपनीय ओधार पर प्रस्तुत सूचना के विषय का एक युक्तिसंगत विवरण है जिससे उस विषय को समझा जा सके । फिर भी, विशेष परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाली पार्टी दर्शा सकती है कि ऐसी सूचना सार का संवेदनशील अंश नहीं है, कारणों का एक ब्यौरा कि क्यों संक्षेपण संभव नहीं है निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि हेतु मुहैया कराना चाहिए ।

19. प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जाँच पर गोपनीयता हेतु निवेदन को प्राधिकारी स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्टि है कि गोपनीयता हेतु निवेदन प्राधिकृत नहीं है अथवा सूचना प्रदायक या तो सूचना सार्वजनिक करने को अनिच्छुक है या सामान्य अथवा संक्षिप्त रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत कर रहा है, इस तरह की सूचना की अवहेलना कर सकते हैं ।

20. उसके एक अर्थपूर्ण अगोपनीय रूपान्तर के बिना अथवा गोपनीयता माँग के लिए एक उचित कारण ब्यौरा दिए बिना किसी तरह का निवेदन निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा दर्ज नहीं किया जाएगा । निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्टि होने की स्थिति में तथा प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता स्वीकार करते हुए, इस तरह की सूचना प्रदान करने वाली पार्टी के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इसे किसी पार्टी को नहीं बताएगा ।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2011

Subject: Initiation of Anti-Dumping investigation concerning imports of Choline Chloride from China PR.

F. No. 14/09/2011-DGAD.—M/s. Jubilant Life Sciences Ltd., Noida have filed a petition, on behalf of the domestic industry, in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping duty on dumped articles and for determination of duty) Rules, 1995 (hereinafter referred to as Rules) before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) alleging dumping of Choline Chloride from People's Republic of China and have requested for Anti-Dumping investigation and levy of Anti-Dumping measures.

2. Domestic industry standing: The petition has been filed by M/s Jubilant Life Sciences Ltd. having corporate office at Plot No. 1-A, Sector-16-A, Institutional Area, Noida - 201301 and manufacturing facilities for manufacture of Choline Chloride at Samlava, Vadodara. M/s Jubilant Life Sciences Ltd, the applicant accounts for a major proportion of the domestic production of Choline Chloride in the country. Therefore, the applicant satisfies the standing to file the petition on behalf of the domestic industry as per Rule 5(a) and (b) and Rule 2 (b).

3. Product involved: The product under consideration in the present investigation is Choline Chloride of all forms and concentrations used for animal feed (herein referred to as subject goods). Choline Chloride is a quaternary ammonium salt which is colourless, viscous and strongly alkaline. It is used as additive in animal feed. The product is classified under Customs Sub-heading 2309.9010 and 2923.1000 of the Customs Tariff Act, 1975. The classification is however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.~

4. Domestic Like Article: The Applicant has claimed that there is no known significant difference in the subject goods produced by the Indian industry and the subject goods exported from the subject countries. The subject goods produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. Thus, the subject goods produced by the Applicant are being treated as like article to the product under consideration imported from the subject country within the meaning of the AD Rules for the purpose of this investigation.

5. Country involved: The country involved in the present investigation is People's Republic of China (herein referred to as subject country).

6. Normal value: The applicant has stated that China PR is a non-market economy country and no country has granted market economy status to China after following elaborate evaluation parameters. It has been further mentioned by the applicant that India has treated China PR as a non market economy country practically in all investigations initiated against China and therefore it should be treated as non-market economy country in the present investigation also. The applicant has stated that in the absence of availability of information in the public domain, the applicant was not in a position to compute the normal value on the basis of price or constructed value in a market economy third country and therefore has constructed the normal value. The Authority has *prima-facie* considered the normal value of subject goods in subject country on the basis of constructed value for the purpose of the initiation of this investigation.

7. Export price: The Applicant has determined the export prices based on the data compiled by IBIS, Mumbai. The export prices have been adjusted for ocean freight, marine insurance, port handling and inland transportation etc to arrive at net export price at ex-factory level.

8. Dumping margin: The applicant has provided sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the net export prices, *prima-facie* indicating that the subject goods originating in or exported from the subject country are being dumped, to justify initiation of an antidumping investigation.

9. 'Injury' and causal link: The Applicant has claimed material injury and threat of material injury as a result of the alleged dumping. It has been claimed that the imports have increased in absolute terms and in relation to consumption in India and that the imports are significantly undercutting the prices of the domestic industry and as well depressing the prices of the domestic industry. The Applicant has further claimed deterioration in the performance of the domestic industry in terms of, market share, profits and return on capital employed.

10. There is sufficient evidence of the 'injury' being suffered by the domestic industry caused by the dumped imports from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation in terms of the AD Rules.

11. Initiation of Anti Dumping Investigation: In view of the foregoing, the Authority finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods from the subject country, 'injury' to the domestic industry and causal link between the dumping and 'injury' exists to justify initiation of an anti-dumping investigation. Accordingly, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent 'injury' to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the AD Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping measure, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

12. Period of investigation: The period of investigation for the purpose of present investigation is **1st April 2010 to 31st March 2011**. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2007-March 2008, April 2008-March 2009, April 2009-March 2010 and the Period of Investigation (POI) viz. **1st April 2010 to 31st March 2011**. For threat of material injury, the data beyond the POI may also be examined.

13. Submission of information: The known exporters in the subject countries and their Governments through their Embassy/Economic and Cultural Centre in India, importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time-limit set out below and write to:

**The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Room No.240, Udyog Bhawan, New Delhi -110107.**

14. Time limit: Any information relating to this investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the above mentioned address, not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this

notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the 'facts available' on record in accordance with the AD Rules.

15. Submission of information on Confidential basis: In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/ submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non-Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

16. Information supplied without any mark shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies each of the confidential version and the non-confidential version must be submitted.

17. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

18. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out/ summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible of summary, a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Designated Authority.

19. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Designated Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

20. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Designated Authority. The Designated Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority